

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग—02

देहरादून: दिनांक २४ जनवरी, 2015:

विषय— वित्तीय वर्ष 2014–15 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मैदानी तालाब निर्माण एवं पर्वतीय तालाब निर्माण आदि की स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—941/अनु०जाति (SCSP)/2014–15, दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में मत्स्य विभाग को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अन्तर्गत मत्स्य पालन संबंधी योजना कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु रु० 15.00 लाख (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इस आहरण कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान प्रदान करते हैं :—

(धनराशि रु० 10 लाख में)

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि
1.	मैदानी तालाब निर्माण	5.00
2.	पर्वतीय तालाब निर्माण	10.00
	कुल योग:—	15.00

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, मत्स्य द्वारा करके आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
3. मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०—०८ पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31—०३—२०१५ तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेग। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा, ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सकेगा।
 7. किसी भी क्र्य/विक्र्य हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रॉल्स 2008, (समय-समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी०जी.एसन.एन.डी. की दरें, टेप्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
 8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- 2— उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-00-आयोजनागत-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-03-मत्स्य पालन संबंधी कार्यक्रम-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।
- 3— यह आदेश वित्त विभाग के अधारस्तकम् संख्या-1055 /XXVII(1)/2014 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या— ३६ (1)/XV-2/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मंत्री मत्स्य विभाग को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।